

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

TEN
RUPEES

रु. 10

Rs. 10



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

41AB 499366

भारत का एक पुराना मुद्रा प्रमाणिका
24/1/77, डा. मंगल, वाल्मीकी गली गंधी रोड बदायुँ
जिला बागपत पिन 200075
मि. अशोक

सत्य प्रतिलिपि

वसिष्ठ
कानून
कानून, न्यायालय तथा चिट्ठा सेवा

03-472

नियमावली

- 1- संस्था का नाम : सर्व शिक्षा प्रसार सेवा समिति।
- 2- संस्था का पूरा पता : 24/127, डा0 संजय वाली गली गांधी रोड, बडीत, जिला- बागपत।
- 3- संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश होगा।
- 4- संस्था के उद्देश्य : स्मृति-पत्र के अनुसार होंगे।
- 5- संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :-

क- सदस्यता :-

जो सज्जन 18 वर्ष से अधिक आयु का हो, नैतिक आचरण वाला हो, दिवालिया न हो, पागल न हो, सर्वोदय विचार वाला हो, संस्था के उद्देश्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता हो, संस्था का सदस्य बन सकता है।

ख- सदस्यों के वर्ग :-



अ- आजीवन सदस्य :-

जो सज्जन क्रमांक 5 (क) के अनुसार योग्यता रखते हुए उसने संस्था को एक मुश्त 101000/- रु0 (एक लाख एक हजार रुपये) नकद या इससे अधिक सम्पत्ति दान स्वरूप देगा, आजीवन सदस्य कहलायेगा। प्रथम प्रबन्धसमिति के गठन के बाद किसी व्यक्ति को आजीवन सदस्य बनने के लिए समिति के चार पदाधिकारी की स्वीकृति लेकर प्रार्थना पत्र प्रबन्धक को देना होगा जिसे स्वीकृत करने के लिए प्रबन्धसमिति की मीटिंग में प्रस्तुत करना होगा। जिसपर स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय होगा। आजीवन सदस्य अपने जीवन-काल में किसी भी सदस्य/सज्जन को अपने स्थान पर मनोनित कर सकते हैं, उनके लिए भुक्त देय नहीं होगा। उनकी स्मृति मृत्यु की तिथि पर उनके स्थान पर उनका वारिस आजीवन सदस्य होगा।

51/2 प्रथम 12 जे 9

51/2 प्रथम 12 जे 9

51/2 प्रथम 12 जे 9

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सचिव/अध्यक्ष
कार्यालय डा0 संजय वाली गली गांधी रोड
बागपत जिला- बागपत

03-4-12

व- सामान्य सदस्य :-

जो सज्जन क्रमांक 5 (क) के अनुसार योग्यता रखते हुए उसने संस्था को एक मुश्त 151/-₹80 नकद वार्षिक शुल्क या इससे अधिक सम्यक्ति दान स्वरूप देगा, सामान्य सदस्य कहलायेगा ।

6- सदस्यता की समाप्ति :-

1- सदस्य की मृत्यु होने पर ।

2- सदस्य द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने पर ।

3- संस्था की सदस्यता शुल्क अदा न करने पर। (सामान्य सदस्य) के लिए

4- सदस्य को दिवालिया अथवा पागल घोषित होने पर।

5- संस्था के विरुद्ध कार्यों में संलिप्त पाये जाने पर।

7- संस्था के अंग :-

क- साधारण सभा।

ख- प्रबन्धकारिणी समिति।

8- साधारण सभा :-

क-गठन:-

संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर बनाया गया समूह साधारण सभा कहलायेगी ।

ख-वैठक :-

साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार एवं विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

ग-सूचना :-

सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी, सूचना डाक या स्पेशल मैसेजर द्वारा दी जायेगी ।

घ-कोरम :-

साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल संख्या का दो तिहाई होगा, कोरम के अभाव में स्थगित की गयी बैठक के लिए कोरम की पायन्दी न होगी, यदि उन्ही विषयों पर विचार होता हो ।

ड- विशेष वार्षिक अधिवेशन :-

संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार हुआ करेगा जिसकी तिथि प्रबन्धसमिति द्वारा निर्धारित की जायेगी।

प्राप्त हुआ है

5/12/2019

5/12/2019

Royal

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक/अध्यक्ष

कल्याण नगरी गिरिस्तूप

कल्याण नगरी गिरिस्तूप

03-412

घ-साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- 1- संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना ।
- 2- संस्था के आय व्यय की रिपोर्ट, बजट आदि को पास करना ।
- 3- संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन 2/3 बहुमत से करना।
- 4- संस्था की नीति निर्धारित करना ।
- 5- संस्था के ग्रन्थ सदस्यों को निकालना ।

9- प्रबन्धकारिणी समिति :-



क-गठन :-

संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति के चुनाव में वोट देने का अधिकार केवल आजीवन सदस्यों को ही होगा। जिसमें अध्यक्ष- एक, प्रबन्धक- एक, उपप्रबन्धक- एक, कोषाध्यक्ष- एक एवं सदस्यगण- छः से आठ होंगे। जो आवश्यकता पड़ने पर घट-बढ़ सकेगी। सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम दो बार एवं विशेष बैठक कभी भी अध्यक्ष के निर्देशन पर बुलाई जा सकती है।

सामान्य बैठक की सूचना 07 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी, सूचना डाक या स्पेशल मैसेजर द्वारा दी जायेगी ।

घ-कोरम :-

प्रबन्धकारिणी समिति का बैठक का कोरम तीन चौथाई होगा, कोरम के अभाव में स्थगित की गयी बैठक की पाबन्दी न होगी, यदि उन्ही विषयों पर विचार होता हो।

ड-रिक्त पद की पूर्ति :-

प्रबन्धकारिणी समिति में आकस्मिक रिक्त पद होने पर उसकी पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति स्वयं साधारण सभा सदस्यों में से बहुमत द्वारा शेष कार्यकाल की अवधि के लिए कर लेगी ।

च-कार्यकाल :-

प्रबन्धसमिति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

च-प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- 1- संस्था के नियमों-विनियमों में संशोधन करना ।
- 2- संस्था का प्रबन्ध संचालन हेतु कर्मचारियों, अधिकारियों की नियुक्ति करना।

Handwritten signature and text in Hindi, including 'सत्यमेव जयते' and '03-4-12'.

सत्य प्रतिलिपि
परिष्कृत संस्करण / अन्तः
कर्मचारी क्लब रजिस्ट्रार
कर्म, संसाधनात्मक विस्तार
03-4-12

- 3- संस्था की वार्षिक रिपोर्ट, बजट आदि को तैयार करना।
- 4- प्रबन्धकारिणी समिति में आकस्मिक रिक्त पद की पूर्ति करना।
- 5- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दान, चन्दा, ऋण, अनुदान, भूमि, भवन, चल अचल सम्पत्ति विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करना।

10- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

अध्यक्ष :-

- 1- संस्था की सभी प्रकार की बैठकों, सभाओं की अध्यक्षता करना।
- 2- सभाओं, कार्यक्रमों आदि के लिए दिनांक, समय का निर्धारण कर सूचना जारी करना।
- 3- समान मत होने पर अपना निर्णायक मत देना।
- 4- संस्था के हित में कार्य करना।

प्रबन्धक :-

- 1- संस्था के अभिलेखों का रख रखाव करना व मीटिंग की कार्यवाही को रजिस्टर में दर्ज कराना, अभिलेख पूर्ण कराना।
- संस्था के अन्तर्गत संचालित स्कूल यूनिट आदि के संचालन हेतु समस्त प्रकार की संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
- संस्था के समस्त वाउचरों, अभिलेखों पर हस्ताक्षर करना एवं उनको आवश्यकता पड़ने पर प्रमाणित भी करना।
- संस्था के द्वारा संचालित यूनिट, संस्थान, स्कूल आदि के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतनवृद्धि, पदोन्नति, डिमोशन आदि सम्बन्धी कार्यवाही करना।
- 5- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अध्यक्ष के साथ मिलकर दान-अनुदान, चन्दा, ऋण, चल अचल सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु सरकारी/गैर सरकारी कार्यालयों, विभागों, बैंक आदि से सम्पर्क कर प्राप्त करना। संस्था के हित में कार्य करना व संस्था की चल व अचल सम्पत्ति को बन्धक रखकर बैंक आदि से संस्था की उद्देश्य की पूर्ति हेतु ऋण प्राप्त करना।



प्राप्त ५ अगस्त २०१२

SK 9419

Royal

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक/अध्यक्ष
कार्यालय डीटी रजिस्ट्रार
संस्था सहायक तब विरत मेरठ

03/14/12

- 6- संस्था के सदस्य/ कर्मचारी के त्याग-पत्र को अध्यक्ष की स्वीकृत के बाद संस्तुति करना।

उपप्रवन्धक :-

प्रवन्धक की अनुपस्थिति में उनके अधिकार एवं कार्य उपप्रवन्धक को निहित होंगे।

कोषाध्यक्ष :-

- 1- संस्था के केश से सम्बन्धित सभी अभिलेख तैयार करना, उनमें धनराशि का इन्द्राज करना।

संस्था के आय व्यय की रिपोर्ट, बजट तैयार कराकर बैठक में प्रस्तावित करना।

अध्यक्ष तथा प्रवन्धक के द्वारा सौंपे गये कार्य करना।

11-

नियमो-विनियमों में संशोधन प्रक्रिया



संस्था के नियमो-विनियमों में संशोधन प्रक्रिया प्रवन्धसमिति के अनुमोदन होने के दस दिनों बाद ~~अध्यक्ष~~ ^{साधारण सभा} की बैठक में दो तिहाई बहुमत पूर्ण होने पर संशोधन/ परिवर्तन मान्य होगा।

12-

संस्था का कोष :-

संस्था का कोष संस्था के नाम से किसी भी बैंक अथवा डाकघर में रखा जायेगा जिसका संचालन संस्था के प्रवन्धक एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

13-

आय व्यय लेखा परीक्षण :-

संस्था के आय व्यय का वार्षिक आडिट प्रवन्धसमिति द्वारा नियुक्त आडिटर अथवा सीओएओ द्वारा कराया जायेगा, जो कि पहली अप्रैल से 31 मार्च तक का होगा।

14-

कानूनी कार्यवाही :-

संस्था की समस्त कानूनी कार्यवाही प्रवन्धक द्वारा की जायेगी, जो कि संस्था के पंजीकृत कार्यालय के क्षेत्रान्तर्गत की जायेगी।

15-

अभिलेख :-

सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, एजेण्डा, लेजर, केश बुक रसीद बुक आदि जो भी आवश्यक हो, रखे जायेंगे।

प्रीतिका
Sugang
R. B. B. B.

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ अधिकारी/उन्ने
कानूनी रजिस्ट्रार
कानूनी रजिस्ट्रार तथा चिह्न मेक


03-1412

16- विधटन : संस्था की विधटन एवं विधटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सौसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी ।

17- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु :

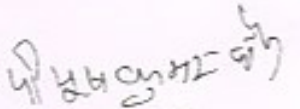


- (अ) चन्दा, दान, ऋण, अनुदान स्वरूप आर्थिक सहायता प्राप्त करना ।
- (ब) किसी भूमि, भवन तथा चल-अचल सम्पत्ति को अनुदान में प्राप्त करना, क्रय करना, व्यवस्थित रखना, हस्तान्तरण करना या पट्टे या किराये या किराये पर लेना या अनुज्ञा द्वारा अन्य साधनों से प्राप्त करना ।
- (स) संस्था की भूमि पर निर्माण, मरम्मत या पहले से बने भवनों में आवश्यक परिवर्तन, परिवर्धन एवं उन्हें बिजली, पानी, फर्नीचर, शौचालय आदि आवश्यक प्रयोगिक सुविधों से सुसज्जित करना ।
- (द) संस्था की भूमि भवन, चल-अचल सम्पत्ति को विक्रय, हस्तान्तरण करना, विनियम करना, बन्धक रखना, पट्टे अथवा किराये पर उठाना या अन्य साधनों से नियमानुसार हस्तान्तरण करना, किन्तु यह सशम न्यायालय की अनुमति के वैध नहीं होगा ।
- (य) शिक्षा के व्यापक विस्तार के लिये जरूरतमन्द संस्थानों को ऋण व अनुदान उपलब्ध कराना ।
- (र) शिक्षा के प्रसार एवं केन्द्रों के निर्माण के लिये ऋण लेना ।

18- आय के स्रोत :-

- 1- भारत सरकार ।
- 2- उत्तर प्रदेश सरकार ।
- 3- अन्य राज्य सरकार ।
- 4- विदेशी संस्थानों ।
- 5- ~~विक्रय~~  ।
- 6- बैंक को ऋण ।
- 7- सदस्यता शुल्क ।
- 8- दान ।
- 9- नाबार्ड, हुडको, आर०एम०के०, एन०एल०सी० से अनुदान या ऋण ।



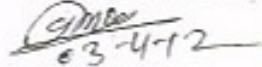
दिनांक 12-12-2007



 SKGPI


सत्यप्रतिलिपि ।

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक / अन्य
 काबालिब / उन्नी रजिस्ट्रार
 कर्ष संसाधन तथा धितस मेरठ


 03-4-12